भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2931

जिसका उत्तर 17 दिसंबर, 2025 को दिया जाना है ।

26 अग्रहायण, 1947 (शक)

आंध्र प्रदेश में वैश्विक क्षमता केन्द्र

2931. श्री बी. के. पार्थसारथी:
श्री बस्तीपति नागराजू:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश सहित देश भर के टियर 2 और टियर 3 शहरों में निर्मित वैश्विक क्षमता केन्द्रों की जिला-वार संख्या क्या है;
(ख) टियर 2 और टियर 3 शहरों के वैश्विक क्षमता केन्द्रों द्वारा वर्ष-वार राज्य-वार कुल कितना वार्षिक राजस्व संग्रह किया गया है;
(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को टियर 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केन्द्रों को बढ़ावा देने के लिए कोई राष्ट्रीय ढांचा तैयार किया गया है;
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ङ) क्या इस ढांचे में केन्द्र सरकार राज्यों को टियर 1 और टियर 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केन्द्र को आकर्षित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करगी; और
(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(च):** भारत सरकार देश भर में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। पिछले 5 वर्षों में इस क्षेत्र के प्रदर्शन और 2024-25 के अनुमानों का उल्लेख नीचे किया गया है:

(अरब डॉलर में)

	2019-20	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25(ई)**
निर्यात राजस्व	147	152	178	194	199.5	224.4
घरेलू राजस्व	44	45	49	51	54.4	58.2
कुल राजस्व	191	196	227	245	254	282.6

(E) = अनुमान *स्रोत: नैसकॉम*

इस मजबूत विकास गति ने भारत में वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) के विस्तार के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है। साथ ही, जीसीसी ने खुद भी आईटी क्षेत्र के इस विकास में योगदान दिया है।

भारत वर्तमान में देश भर में लगभग 2,975 जीसीसी इकाइयों के साथ 1,750 से अधिक वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) को होस्ट करता है। 220 से अधिक इकाइयां टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्थित हैं, जो महानगरीय केंद्रों से परे जीसीसी के बढ़ते विकेंद्रीकरण को दर्शाती हैं।

इन जीसीसी ने मिलकर वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 64.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व अर्जित किया।

उद्योग के अनुमान के अनुसार, भारत का ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) बाजार वर्ष 2030 तक 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। देश में जीसीसी की संख्या वर्ष 2030 तक मौजूदा स्तर से बढ़कर लगभग 2,400-2,550 होने की उम्मीद है

जीसीसी का सुदृढ़ीकरण

जीसीसी इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में टियर- II शहरों में जीसीसी को बढ़ावा देने में राज्यों का मार्गदर्शन करने के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार करने की घोषणा की गई। यह ढांचा प्रतिभा और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता बढ़ाने, उप-कानून सुधारों के निर्माण और उद्योग के साथ सहयोग के लिए तंत्र के उपाय सुझाता है।

आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों ने टियर-2 और टियर-3 शहरों में जीसीसी संचालन को आकर्षित करने और विस्तारित करने के लिए समर्पित जीसीसी या आईटी/आईटीईएस नीतियों को पहले ही अधिसूचित कर दिया है।

प्रस्तावित राष्ट्रीय ढांचे का उद्देश्य राज्यों के लिए एक सक्षम और मार्गदर्शक तंत्र के रूप में कार्य करना है। जीसीसी के लिए वित्तीय प्रोत्साहन राज्य-विशिष्ट नीतियों के माध्यम से लागू किए जाते हैं, जबकि केंद्र सरकार डिजिटल बुनियादी ढांचे, कौशल पहल और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों के माध्यम से इकोसिस्टम का समर्थन करती है।

*****